

**(xiv) राजस्थान में स्थानीय स्वशासन :
ग्रामीण एवं शहरी**

196. पंचायती राज के किस स्तर पर एक "साथिन" का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए 'मानदेय महिला कार्यकर्ता' के रूप में किया जाता है?

- (a) जिला-परिषद (b) पंचायत-समिति
(c) ब्लॉक स्तर (d) ग्राम-पंचायत

Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-C

Ans. (d) : महिला विकास कार्यक्रम की केन्द्र बिन्दु मानदेय प्राप्त ग्राम पंचायत साथिन है। साथिन का चयन ग्राम सभा (ग्राम पंचायत) द्वारा किया जाता है। महिला विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लेने हेतु उन्हें सशक्त बनाना है।

197. निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है?

- (a) पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार (पेसा, PESA) अधिनियम 24 दिसम्बर, 1996 को लागू हुआ।
(b) पेसा (PESA) अधिनियम, दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया।
(c) पेसा (PESA) अधिनियम, अनुसूची-5 के 9 राज्यों में लागू है।
(d) इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है।

Rajasthan CET (G. Level) 2022 Set-C

Ans. (c) : पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (PESA) 1996, दिनांक 24 दिसम्बर, 1996 में लागू किया गया। यह अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग-9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने का लक्ष्य है।

198. राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं?

- (a) 25 (b) 30
(c) 35 (d) 40

VDO-2021 Exam Date 27.12.2021 Shift-II

Ans. (a) — राजस्थान में जिला आयोजना/योजना समिति में 25 सदस्य होते हैं। इसमें 20 निर्वाचित तथा 5 मनोनित सदस्य होते हैं। इन समितियों के गठन, चुनाव, शक्तियाँ और कार्यों से सम्बन्धित विस्तृत प्रावधान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350, 351 और 352 में उपबंधित है। जिला योजना समिति (DPC) का कार्य जिले में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी वार्षिक योजनाओं को समेकित करना है।

199. राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?

- (a) इस योजना का नारा है 'आपणी योजना आपणों विकास' है।
(b) इस योजना में वित्त पोषण के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है।
(c) इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है।
(d) पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज, अभियान किया गया है।

RPSC RAS (Pre) 2021

Ans. (a) : राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में 'आपणी योजना आपणों विकास' योजना का नारा नहीं है। वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में सतत् विकास लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए पंचायतीराज संस्थानों की शासन क्षमता विकसित करने के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा की थी। इसमें पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। इस योजना के वित्त पोषण के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 होता है।

200. राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

- (a) जिला कलेक्टर
(b) जिला प्रमुख
(c) वित्त मंत्री
(d) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**RPSC Kanishta Abhiyanta (Y.V.) 20-05-2022, Shift-II
RPSC College Lecturer (Sanskrit Education) 2015**

Ans. (b) : राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला जिला प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य की जिला आयोजन समिति में भिन्नता है। राजस्थान जिला आयोजन समिति में कुल 25 सदस्य हैं, जिसमें से 20 सदस्य ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, जबकि पाँच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं जिसमें जिला कलेक्टर, एडीएम, कार्यकारी जिला परिषद एवं लोकसभा सदस्य तथा विधानसभा का सदस्य होते हैं।

201. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की किस धारा को संशोधित कर 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है?

- (a) 88 (b) 89
(c) 91 (d) 90

RPSC RAS (Pre) 2021

Ans. (b) : राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 को संशोधित कर 'ग्राम सेवक' के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल, 1994 को लागू हुआ था।

202. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद् में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किये जा सकते हैं?

- (a) 10 (b) 12
(c) 8 (d) 6

RPSC RAS (Pre) 2021